पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में,

लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1190/2023

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.-8993/2023 से उत्पन्न

==========

कुमार मुकेश, प्रेम प्रकाश सिंह का बेटा, गाँव और डाकघर-अमौरा, थाना-काराकट, जिला-रोहतास, बिहार-802214 के निवासी

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम्

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

2. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।

3. सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, विश्वशरैया भवन, पटना।

4. निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।

5. जिला दंडाधिकारी, रोहतास।

6. सचिव, जवाहरलाल नेहरु मार्ग, पटना के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग, 15।

7. अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना।

8. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना।

9. परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना।

10. अतुल श्रीवास्तव, पिता का नाम याचिकाकर्ता को ज्ञात नहीं, निवासी-याचिकाकर्ता को ज्ञात नहीं, अनुक्रमांक 660028 बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 66/2020 के विरुद्ध प्रकाशित अंतिम परिणाम दिनांक 01.06.2023 में क्रम सं. 33।

.....प्रतिवादी/गण

==========

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील-पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोतों की श्रेणी के तहत सहायक प्रोफेसर के रूप में भर्ती के लिए रिट आवेदन को खारिज करना-साक्षात्कार के दौरान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफलता।

आयोजित किया गयाःअपीलकर्ता पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोतों की श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र जमा करने में विफल रहा-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई गई-अपील खारिज कर दी गई।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में,

लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1190/2023

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.-8993/2023 से उत्पन्न

==========

कुमार मुकेश, प्रेम प्रकाश सिंह का बेटा, गाँव और डाकघर-अमौरा, थाना-काराकट, जिला-रोहतास, बिहार-802214 के निवासी

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम्

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

2. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।

3. सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, विश्वशरैया भवन, पटना।

4. निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।

5. जिला दंडाधिकारी, रोहतास।

6. सचिव, जवाहरलाल नेहरु मार्ग, पटना के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग, 15।

7. अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना।

8. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना।

9. परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना।

10. अतुल श्रीवास्तव, पिता का नाम याचिकाकर्ता को ज्ञात नहीं, निवासी-याचिकाकर्ता को ज्ञात नहीं, अनुक्रमांक 660028 बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 66/2020 के विरुद्ध प्रकाशित अंतिम परिणाम दिनांक 01.06.2023 में क्रम सं. 33।

.....प्रतिवादी/गण

==========

उपस्थिति :

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री कुमार कौशिक, अधिवक्ता

बी.पी.एस.सी. के लिए : श्री संजय पांडे, अधिवक्ता

==========

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रॉय

सी.ए.वी. निर्णय

(प्रतिःमाननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रॉय)

तारीखः 07-11-2023

पक्षों को सुना।

2. वर्तमान अपील दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 8993/2023 में पारित 19.09.2023 दिनांकित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है जिससे जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोतों की श्रेणी के अन्तर्गत गणित विषय *'(बिहार लोक सेवा आयोग' द्वारा जारी विज्ञापन संख्या-66/2020)* में सहायक प्रोफेसर के पद पर अपनी बहाली के लिए दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया।

3. संक्षेप में मामला इस प्रकार हैः-

4. अपीलार्थी-याचिकाकर्ता ने पटना विश्वविद्यालय से गणित में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद वर्ष 2013 में जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा से इसी विषय में पीएचडी की।

5. बिहार लोक सेवा आयोग (अब से संक्षिप्त में 'बी.पी.एस.सी.') ने सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों में गणित विषय में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए **06.10.2020** को विज्ञापन संख्या **66/2020** के माध्यम से एक विज्ञापन प्रकाशित किया। विज्ञापन के अनुसार, कुल 126 रिक्तियों का विज्ञापन दिया गया था, जिनमें से दो रिक्तियां पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के पोतों के लिए आरक्षित थीं।

6. अपीलार्थी-याचिकाकर्ता पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड की उक्त श्रेणी के तहत पात्र होने के कारण विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर दिया। अपने दावे के समर्थन में, उन्होंने जिला दंडाधिकारी, पटना के हस्ताक्षर के तहत बिहार सरकार द्वारा जारी वर्ष 2008 का पहचान पत्र संलग्न किया।

7. दो साल बाद, 'बी. पी. एस. सी.' ने लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जो **23.10.2022** को होनी थी। अपीलार्थी-याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ और उसे सफल घोषित किया गया, जिसका परिणाम **27.01.2023** को प्रकाशित किया गया था।

8. इसके बाद, 'बी.पी.एस.सी.' ने **03.02.2023** को साक्षात्कार कार्यक्रम प्रकाशित किया, जिसके अनुसार अपीलार्थी-याचिकाकर्ता को **01.03.2023** को उपस्थित होना था। निर्देशों के अनुसार, साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

9. इस प्रकार प्रकाशित साक्षात्कार कार्यक्रम के बाद साक्षात्कार पत्र आया जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद ही अपीलार्थी-याचिकाकर्ता ने जिला दंडाधिकारी, पटना (पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोतों के संबंध में) से प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने का फैसला किया और इस जानकारी पर कि यह उसे उसके गृह जिले से प्राप्त किया जाना है, बाद में सासाराम में रोहतास के जिला दंडाधिकारी के समक्ष **20.02.2023** को आवेदन प्रस्तुत किया।

10. चूंकि वह समय पर प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता पहचान पत्र के साथ **01.03.2023** को साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुआ और 'बी. पी. एस. सी.' के अधिकारियों को सूचित किया कि उसने पहले ही प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया है और एक बार इसे प्राप्त करने के बाद वह इसे प्रदान करेगा।

11. अंत में उन्होंने **07.03.2023** को प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जिसके बाद उन्होंने इसे **10.03.2023** को 'BPSC' को भेज दिया (क्योंकि 'HOLI' के कारण कार्यालय 08.03.2023 और 09.03.2023 पर बंद था)। अपीलार्थी-याचिकाकर्ता भी **11.03.2023** को कार्यालय गया और मूल प्रति जमा की।

12. अंतिम परिणाम **01.06.2023** को प्रकाशित किया गया था जिसमें कुल 108 उम्मीदवारों का चयन किया गया था, जिनमें से 45 उम्मीदवारों का चयन सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के तहत किया गया था। जहाँ तक स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के पोते-पोतियों का संबंध है, अपीलार्थी-याचिकाकर्ता के बजाय प्रतिवादी संख्या 10, अतुल श्रीवास्तव का चयन किया गया।

13. अपीलार्थी-याचिकाकर्ता की शिकायत है कि उन उम्मीदवारों के मामले में जिन्होंने 01.07.2009 से पहले अपनी Ph.D. उत्तीर्ण करने के बाद छूट मांगी थी, उन्हें 'बी.पी.एस.सी.' द्वारा जारी दिनांकित 06.04.2023 और 26.04.2023 के अनुसार अपने-अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था, जबकि उनके मामले को नजरअंदाज कर दिया गया था।

14. उक्त श्रेणी के तहत 'बी. पी. एस. सी.' द्वारा अपनी उम्मीदवारी से इनकार किए जाने से नाराज, अपीलार्थी-याचिकाकर्ता ने दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 8993/2023 को प्राथमिकता दी।

15. मामले के समर्थन में रखे गए तर्क के अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों को भी रिट न्यायालय के समक्ष उद्धृत किया गया था जो इस प्रकार हैंः

(i) **धीरेंद्र सिंह पालीवाल बनाम संघ लोक सेवा आयोग (2017) 11 एस. सी. सी. 276** में प्रतिवेदित

(ii) **डॉली छांडा बनाम अध्यक्ष, जे. ई. ई. और अन्य। (2005) 9 एस. सी. सी. 779** में प्रतिवेदित;

(iii) **संघ लोक सेवा आयोग बनाम ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव ने (2012) 1 एस. सी. सी. 537** में प्रतिवेदित

16. 'बी.पी.एस.सी. ने रिट न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता के दावे का विरोध करते हुए कहा कि विज्ञापन संख्या 66/2022 में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के पोते (जिन्हें केंद्र सरकार से पेंशन मिलती है) हालांकि लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, उन्हें जिला दंडाधिकारी या साक्षात्कार के समय

उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत जारी प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक था। इसके अलावा, पहचान पत्र मांगे गए प्रमाण पत्र के दायरे में नहीं आता है। 'बी. पी. एस. सी.' का तर्क था कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता ने प्रमाण पत्र जमा करने के बजाय आवेदन के साथ अपनी आई. डी. संलग्न की और दो साल बाद भी, साक्षात्कार के समय, वह प्रमाण पत्र जमा करने में विफल रहा।

17. 'बी.पी.एस.सी.' का रुख यह है/था कि 03.02.2023 को प्रकाशित साक्षात्कार कार्यक्रम ने पैराग्राफ 3 (xix) में यह स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र को मूल से सत्यापित किया जाना है और आई. डी. पर विचार नहीं किया जाएगा।

18. हालाँकि, चूंकि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता साक्षात्कार के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा, इसलिए उसे स्वतंत्रता सेनानी के पोतों की श्रेणी में उचित रूप से नहीं माना गया और सीट प्रतिवादी सं-10 को मिल गया।

19. जहाँ तक अन्य उम्मीदवार को दिए गए राहत के आरोप का संबंध है, विवाद यह था कि यह उन उम्मीदवारों से संबंधित है जो 11.07.2009 से पहले अपनी पीएचडी पूरी करने के संबंध में अपना मुक्ति प्रमाण पत्र जमा नहीं कर सके थे। 'बी.पी.एस.सी.' का रुख यह है कि जिन लोगों ने पहले ही 11.07.2009 से पहले उक्त डिग्री प्राप्त कर ली थी, वे यू. जी. सी. अधिसूचना दिनांक 18.07.2018 के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव या डीन द्वारा जारी किया जाने वाला मुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहते थे। इस प्रकार अपीलार्थी-याचिकाकर्ता जो किसी विशेष श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा कर रहा था, वह खुद को उन उम्मीदवारों के बराबर नहीं ठहरा सकता है।

20. विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले को संभाला और मामले के तथ्यों पर ध्यान देने के साथ-साथ दिनांकित 19.09.2023 के आदेश में उल्लिखित निर्णयों पर भी ध्यान देने के बाद याचिका को खारिज कर दिया और समापन भाग इस प्रकार पढ़ा गयाः

> *"28. इस स्तर पर, इस न्यायालय को **भारत पेट्रोलियम लिमिटेड निगम एवं एक अन्य बनाम एन. आर. वैरामणि और एक अन्य, (2004) 8 एस. सी. सी. 579** में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की याद दिलाई जाती है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि न्यायालय के निर्णयों को यूक्लिड के प्रमेय की तरह उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मामले के तथ्यों में थोड़ा सा बदलाव अदालत की राय में भारी अंतर लाएगा।*
>
> *29. वर्तमान मामले में, इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता पूरी तरह से जानता था कि उसे क्या करने की आवश्यकता थी और विज्ञापन के तहत क्या आवश्यकता है। मान लीजिए, उनके पास आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं था और उन्होंने उसे अपलोड नहीं किया था और साक्षात्कार के समय उनके पास वह नहीं था। उनका दावा है कि उन्होंने साक्षात्कार समाप्त होने के कुछ दिनों बाद इसे डाक द्वारा और भौतिक रूप से भेजा था।*
>
> *30. ऐसे मामले में, यदि यह न्यायालय आयोग द्वारा प्रकाशित परिणाम में हस्तक्षेप करने के लिए अपने असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, तो यह केवल विज्ञापन में मौजूद स्पष्ट शर्त का उल्लंघन करके किया जा सकता है। यह न्यायालय ऐसा करने से खुद को रोक लेगा क्योंकि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि रिट अदालतें अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी आत्म-संयम संहिता द्वारा निर्देशित होती हैं। इस न्यायालय के लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप एक खराब मिसाल पैदा कर सकता है।*

31. उपरोक्त कारणों से, इस रिट आवेदन को खारिज कर दिया जाता है। "

21. रिट न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.09.2023 के उक्त आदेश से व्यथित होकर, वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी गई है।

22. पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना।

23. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री कुमार कौशिक प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश इस तथ्य को ध्यान में रखने में विफल रहे कि जब उम्मीदवारों को नेट परीक्षा प्रमाण पत्र जमा करने का अवसर दिया गया था, तो उन्हें बाद में स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड का प्रमाण पत्र जमा करने से मना करने का कोई कारण नहीं था।

24. उनका आगे निवेदन है कि उम्मीदवारों पर दो अलग-अलग मापदंड लागू नहीं किए जा सकते हैं और यह स्पष्ट रूप से भेदभाव और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

25. उनके अनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश **धीरेंद्र सिंह पालीवाल बनाम संघ लोक सेवा आयोग (ऊपर) डॉली छांडा बनाम अध्यक्ष, जे. ई. ई. और अन्य** (ऊपर) और **संघ लोक सेवा आयोग बनाम ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव** (ऊपर) के मामले में उचित दृष्टिकोण से विचार करने में विफल रहे हैं।

26. विद्वान वकील यह प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

27. दूसरी ओर 'बीपीएससी' की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री संजय पांडे प्रस्तुत करते हैं कि विज्ञापन संख्या 66/2020 वर्ष 2020 में जारी किया गया था,

परीक्षा दो साल बाद वर्ष 2022 में हुई थी और साक्षात्कार फरवरी-मार्च, 2023 के महीने में हुआ था।

28. 'बी.पी.एस.सी. ने विज्ञापन में ही स्पष्ट रूप से शामिल किया था; बहुत पहले और फिर साक्षात्कार के बुलावा पत्र में प्रकाशित किया गया था कि स्वतंत्रता सेनानी के पोतों की श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए, जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, साक्षात्कार के समय आवश्यक है।

29. जब अपीलार्थी 01.03.2023 पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए तो ऐसा करने में विफल रहने के कारण, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के पोतों की श्रेणी के तहत उचित रूप से नहीं माना गया और सीट अतुल श्रीवास्तव (प्रतिवादी सं.10) को मिला। इस प्रकार, वह प्रस्तुत करता है कि रिट न्यायालय तर्कपूर्ण आदेश पारित करने में पूरी तरह से उचित था, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अपील खारिज किए जाने के लिए उपयुक्त है।

30. पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने और अभिलेखों के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का अध्ययन करने के बाद, हमें इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए किः

(i) विज्ञापन सं **66/2020 बी.पी.एस.सी. द्वारा 06.10.2020** को जारी किया गया था

(ii) आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि था/थे **18.11.2020;**

(iii) खंड 9 (एन) में स्पष्ट रूप से कहा गया कि स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी के पोते-पोतियों के दावे से संबंधित जिला दंडाधिकारी या अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ जमा करनी होगी।

(iv) इसके बजाय अपीलार्थी-याचिकाकर्ता ने अपने आई.डी. कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत किया।

31. आगे यह ध्यान देने योग्य है किः

(i) परीक्षा दो साल बाद **23.10.2022** को हुई।

(ii) अपीलार्थी-याचिकाकर्ता को लिखित परीक्षा में सफल घोषित किया गया था।

(iii) परिणाम **27.01.2023** को प्रकाशित किया गया था;

(iv) **03.02.2023** को प्रकाशित अनुसूची के अनुसार, साक्षात्कार **28.02.2023** से लेकर **04.03.2023** तक आयोजित हुआ

(v) इसके अलावा, उम्मीदवारों को साक्षात्कार की तारीख को आरक्षण के लिए योग्यता/दावे से संबंधित मूल दस्तावेज लाने का निर्देश दिया गया था।

(vi) यह स्पष्ट किया गया था कि आई. डी. स्वीकार्य नहीं होगा

(vii) अपीलार्थी-याचिकाकर्ता बिना प्रमाणपत्र के साक्षात्कार के लिए **01.03.2023** को उपस्थित हुआ;

(viii) **'बी.पी.एस.सी.'** ने उपरोक्त परिस्थितियों में स्वतंत्रता सेनानी के पोतों की श्रेणी के तहत उनके मामले पर विचार नहीं करने का फैसला किया;

(ix) उस श्रेणी के तहत सीट प्रतिवादी सं.-10 को मिला।

(x) वह अंततः अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे।

32. अपीलार्थी-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि उन्हें एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में वर्षों का समय क्यों लगा, जो उनके लिए स्वतंत्रता सेनानी के पोतों की श्रेणी के तहत विचार किए जाने के लिए आवश्यक था।

33. इसके अलावा यह अपीलार्थी-याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि उसने कोई आवेदन किया/जिला दंडाधिकारी, रोहतास, सासाराम के कार्यालय से संपर्क किया और/या उसे 01.03.2023 से पहले प्रमाण पत्र देने के लिए कोई तात्कालिकता दिखाई ताकि वह इसे साक्षात्कार के समय जमा कर सके।

34. उन्होंने इसे 07.03.2023 को आराम से प्राप्त किया और 11.03.2023 को, यानी अपने साक्षात्कार की तिथि 01.03.2023 के समाप्त होने के दस दिन बाद प्रस्तुत किया। उक्त परिस्थितियों में, वह उन्हें सीट से वंचित करने के कारण से खुद को दोषमुक्त नहीं कर सकते हैं और स्वतंत्रता सेनानी वार्ड श्रेणी के तहत उनके दावे पर विचार नहीं करने में प्रतिवादी पूरी तरह से उचित थे।

35. जहां तक उन उम्मीदवारों के लिए समय के विस्तार का संबंध है जो 11.07.2009 से पहले अपनी Ph. D पूरी करने के छूट प्रमाण पत्र जमा नहीं कर सके थे, 'BPSC' का स्पष्ट रुख यह है कि क्योंकि वे पहले ही अपनी Ph. D पूरी कर चुके थे और आवेदन करने के लिए विधिवत योग्य थे। आवेदन में, उन्हें मुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया था जो अपीलार्थी के मामले से अलग और भिन्न है जो आरक्षित श्रेणी के तहत एक सीट चाहता था और इस प्रकार वह प्रमाण

पत्र प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्यबद्ध था, जिससे वह साक्षात्कार के समय उस श्रेणी के तहत विचार हेतु पात्र बन जाता है।

36. **धीरेंद्र सिंह पालीवाल बनाम यूपीएससी** (उपरोक्त) के मामले के संदर्भ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पैराग्राफ 14 को इस प्रकार पढ़ा गयाः-

> *"14. संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार करने और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय के कथन को नोट करने के बाद, हमारा विचार है कि विज्ञापन में उल्लिखित विवरण के आलोक में, उक्त विज्ञापन के जवाब में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण और बाद में विषय के रूप में प्राणी विज्ञान के साथ बी. एस. सी. की डिग्री प्राप्त करने के लिए डिग्री प्रमाण पत्र का उत्पादन, अपीलार्थी के पास आवश्यक योग्यताओं के मामले में पूरी की जाने वाली आवश्यकता का पर्याप्त अनुपालन था। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत को लागू करते हुए, प्रत्यर्थी आयोग को आवेदन पर विचार करना चाहिए था और इससे भी अधिक तब जब अपीलार्थी पहले से ही वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की सेवाओं में था और उसकी आवश्यक योग्यताएं बायोडाटा के रुप में बहत अधिक अभिलेख पर थी और इसलिए न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुसार जब प्रत्यर्थी आयोग ने अपीलार्थी का साक्षात्कार लिया और उसे सभी निष्पक्षता में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद के लिए चुने जाने और नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त पाया, तो अपीलार्थी को नियुक्त किया जाना चाहिए था।*

37. उस मामले में, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) के पद के लिए, उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था

क्योंकि बी. एस. सी. प्रमाण पत्र से, यह स्पष्ट नहीं था कि उसने प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया था या नहीं। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि वह पहले से ही 'एफएसएल' में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में काम कर रहे थे और उनके जीवनवृत्त को माध्यमिक से लेकर स्नातकोत्तर तक की उनकी पूरी योग्यता वाले विभाग द्वारा बनाए रखा गया था और उस पृष्ठभूमि में, अपील की अनुमति दी गई थी।

38. अपीलार्थी-याचिकाकर्ता का मामला उपरोक्त मामले से पूरी तरह से अलग है और वह खुद की बराबरी नहीं कर सकता है जब उसके पास साक्षात्कार के समय श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाला प्रमाण पत्र नहीं था।

39. जहां तक **डॉली छांडा बनाम अध्यक्ष, जे. ई. ई. और अन्य** (उपरोक्त) के मामले का संबंध है, उस मामले में, हालांकि लड़की के पास अपने पिता, एक पूर्व सैनिक से संबंधित दोषपूर्ण प्रमाण पत्र था, यद्यपि जिस दिन दूसरा परामर्श आयोजित हुआ, उस दिन संशोधित प्रमाण पत्र से लैस थी। चूंकि अधिकारी इस पर ध्यान देने में विफल रहे और उनके मामले पर विचार नहीं किया, इसलिए प्रार्थना की अनुमति दी गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिला सैनिक बोर्ड द्वारा की गई गलती के लिए उन्हें पीड़ित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, वह एक रैंक धारक थी और दूसरी परामर्श के समय सही प्रमाण पत्र से लैस थी, उस पर विचार किया जाना चाहिए था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैंः

> "9. अपीलार्थी निस्संदेह आरक्षित एम. आई. श्रेणी से संबंधित था। वह एक बहुत ही विनम्र पृष्ठभूमि से आती हैं, उनके पिता सशस्त्र बलों में केवल एक नायक थे। हो सकता है कि उन्होंने

उस गलती पर ध्यान न दिया हो जो जिला सैनिक बोर्ड द्वारा दिनांक 29-6-2003 का पहला प्रमाण पत्र जारी करते समय की गई थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब अपीलार्थी दूसरी परामर्श के चरण में सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है तो उसे उसके देय से वंचित कर दिया जाना चाहिए। जिन लोगों ने अपीलार्थी से कम रैंक हासिल की है, उन्हें पहले ही भर्ती किया जा चुका है। अपीलार्थी के प्रवेश से इनकार करने में अधिकारियों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अवैध है।

10. अपीलार्थी ने जे. ई. ई.-2003 में योग्यता प्राप्त की थी लेकिन उक्त शैक्षणिक वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका है। लेकिन इस स्थिति के लिए गलती उत्तरदाताओं की है, जिन्होंने अत्यधिक तकनीकी और कठोर रवैया अपनाया, न कि अपीलार्थी की। इसलिए हमारी यह राय है कि अपीलार्थी को चालू शैक्षणिक वर्ष में किसी भी राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाना चाहिए।

11. तदनुसार अपील की अनुमति लागत के साथ दी जाती है। उच्च न्यायालय के 31-10-2003 दिनांकित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलार्थी को राज्य के किसी भी मेडिकल कॉलेज में तुरंत प्रवेश दें। यदि राज्य की सीटें पहले ही भरी जा चुकी हैं, तो उनके लिए एक अतिरिक्त सीट बनाई जाएगी। ”

40. अपीलार्थी-याचिकाकर्ता का मामला **डॉली छंदा** (ऊपर) के मामले के आसपास कहीं नहीं आता है। इसमें उम्मीदवार के पास एक प्रमाण पत्र था, हालांकि जिला सैनिक बोर्ड द्वारा गलत प्रविष्टि के कारण, पहली परामर्श के समय इस पर विचार नहीं किया गया था। हालाँकि, जब तक दूसरी परामर्श हुई, तब तक उनके पास जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी एक सही प्रमाण पत्र था। अपीलार्थी-याचिकाकर्ता के मामले में, उन्होंने न तो इसे अपने आवेदन के साथ संलग्न किया और न ही साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया। यह दोहराया जाना चाहिए कि जब से विज्ञापन वर्ष 2020 में जारी किया गया था, तब से लेकर जब साक्षात्कार हुआ, तब तक अपीलार्थी-याचिकाकर्ता के पास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दो साल से अधिक समय था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा।

41. जहाँ तक **संघ सेवा आयोग बनाम ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव** (ऊपर) से संबंधित मामला है उस मामले में, उम्मीदवार हालांकि अपनी कानून की डिग्री जमा नहीं कर सका, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो दर्शाता है कि उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में तीन साल का अध्ययन किया था, उसके आवेदन का हिस्सा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मानते हुए कि चयन प्रक्रिया में, उसे योग्यता के आधार पर क्रम संख्या 1 पर रखा गया था, उसकी नियुक्ति के लिए निर्देश दिया।

42. इस प्रकार, उस मामले में, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के मद्देनजर, यह स्पष्ट था कि उनके पास कानून की डिग्री थी। हालांकि, वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोतों की श्रेणी के तहत आरक्षण चाहता था और इसलिए लाभ प्राप्त करने के लिए एक प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक था। इस प्रकार यह मामला भी उनके बचाव में नहीं आता है।

43. एक उम्मीदवार (अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता पठित) को वर्षों तक प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, साक्षात्कार समाप्त होने के बाद दस्तावेज़ के साथ आ सकते हैं और फिर अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने का दावा कर सकते हैं जो प्रतिवादी सं.10 को जा चुका है।

44. इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में, जो परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं, वे उन्मूलन की प्रक्रिया से गुजरती हैं और सबसे उपयुक्त को उठाया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 10, अतुल श्रीवास्तव सभी मानदंडों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मेहनती थे और स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड की श्रेणी के तहत पद के लिए अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को पीछे छोड़ दिया।

45. हमें दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 8993/2023 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित 19.09.2023 आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिलती है। याचिका खारिज की जाती है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

नेहा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।